5.8.20

सार्वजनिक व्यय और वितरण :-
(Public expenditure & distribution)

समस्या- वितरणीय असमानताएँ बाज़ार-व्यवस्था का एक शाप हैं। इनसे निम्न तथा पूर्व-निश्चित मौद्रिक आय वाले लोग पीड़ित होते हैं। तुलनात्मक दृष्टि से वितरणीय असमानताओं की समस्या विकसित अर्थव्यवस्था के लिए कम कष्टदायक होती है क्योंकि वहाँ पर प्रतिव्यक्ति आय का उच्च स्तर होने के कारण गरीब परिवार भी अपनी दैनिक आवश्यकताएँ सुगमता से पूरी कर सकते हैं तथा उनका जीवन-स्तर स्वीकार्य बना रहता है। परंतु अल्पविकसित देशों में कुल मिलाकर गरीबी की व्यापकता इतनी अधिक होती है कि वहाँ के अधिकतर गरीब लोग दरिद्रता की रेखा से भी नीचे चले जाते हैं। यह एक सर्वमान्य धारणा है कि इस प्रकार की वितरणीय असमानताओं को दूर करने का पूर्ण प्रयत्न किया जाना चाहिए, क्योंकि इनके रहते आर्थिक और सामाजिक विकास का होना निरर्थक है और इनसे इस प्रकार की सामाजिक एवं अन्य समस्याएँ भी उत्पन्न होती हैं। गरीबी और दरिद्रता स्वयं में भी मानवता के लिए किसी शाप से कम नहीं, तथा इनसे यथासंभव छुटकारा पाना ही श्रेयस्कर है।

समाधान संबंधी तर्क - एक मतानुसार, आर्थिक विकास के लिए बचत और निवेश की ऊँची दरों का होना आवश्यक है। और आय तथा धन की वितरणीय असमानताओं को घटाने से ये हतोत्साहित होती हैं। क्योंकि ऊँची आय वाले लोगों की बचत प्रवृत्ति अधिक होती है, अतः उनकी आय के एक अंश का निम्न आय वर्गों को हस्तांतरित किए जाने पर देश में कुल उपभोग व्यय बढ़ जाता है तथा बचत और निवेश घट जाते हैं।

परंतु वितरणीय असमानताएँ बनाए रखने के पक्ष में उपर्युक्त तर्क काफी भ्रामक हैं। आर्थिक विकास केवल पूँजी के अस्तित्व एवं इसके उपयोग का ही प्रतिफल नहीं होता। उसमें श्रम की उत्पादिता का भी उतना ही योगदान रहता है जितना कि अन्य उत्पादन साधनों का। अतः सार्वजनिक व्यय का एक मुख्य उद्देश श्रम की उत्पादिता में वृद्धि लाना होना चाहिए जिसके लिए

Scanned by CamScanner

श्रम-कल्याण पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। इस संदर्भ में विचारणीय है कि गरीबी और दरिद्रता के होते शिक्षण-प्रशिक्षण तो दूर, श्रमिक वर्ग अपनी दैनिक आवश्यकताओं को भी पूरा करने में असमर्थ रहते हैं। ऐसी परिस्थितियों में श्रम की उत्पादिता के उच्चस्तरीय होने का प्रश्न ही नहीं उठता।

असमानताओं की व्युत्पत्ति (Origin) - एक बाज़ार-व्यवस्था में, अन्य कारकों के अतिरिक्त तीन कारक मुख्य रूप से वितरणीय असमानताएँ बढ़ाने में सहायक होते हैं; अर्थात (क) कीमतों में वृद्धि, (ख) निजी संपत्ति की संस्था तथा (ग) उत्तराधिकारिता की संस्था (increase in prices and Institutions of private property and inheritance)

समाधान - यह मानते हुए कि समाज बाज़ार-व्यवस्था का त्याग करना नहीं चाहता, सार्वजनिक व्यय की नीति ऐसी होनी चाहिए जो उपर्युक्त तीनों कारकों की शक्ति को कमज़ोर करने में सहायक बने। इस लक्ष्य की प्राप्ति तभी संभव है जब सार्वजनिक व्यय की नीति कुछ महत्वपूर्ण घटकों का एक उचित मिश्रण हो। इन नीति घटकों की रूपरेखा निम्न प्रकार से होनी चाहिए -

1. गरीबी और दरिद्रता का एक रूप वह है जिसमें निम्न आय के वर्ग क्रय-शक्ति के अभाव में अपनी बुनियादी आवश्यकताओं की वस्तुएँ और सेवाएँ भी नहीं खरीद सकते। अत: ऐसी वस्तुओं को कम दामों पर निम्न आय के वर्गों को मुहैया कराने के लिए उपयुक्त अनुदानों (subsidies) की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक व्यय का एक भाग परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक निर्यात की वस्तुओं पर भी लगाया जा सकता है।

2. रोज़गार में वृद्धि आय की असमानताओं के साथ गरीबी और दरिद्रता घटाने का एक अचूक इलाज है। इसलिए जहाँ एक ओर सरकार को चाहिए कि अपने आवश्यक उपभोग व्यय में कटौती करे, वहीं रोजगार बढ़ाने वाली प्रभावी स्कीमों पर भी व्यय किया जाना चाहिए।

3. एक बाज़ार-व्यवस्था में निम्न आय-वर्ग कई प्रकार से सामाजिक

Scanned by CamScanner

सुरक्षा' के अभाव से पीड़ित होते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं, दृष्टों के लिए पेंशनों आदि जैसे कार्यक्रमों से आय की असमानताओं के कुप्रभावों को किसी हद तक दूर किया जा सकता है।

4. सरकार के व्यय का एक बड़ा भाग विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं के क्रय करने पर लग जाता है। सरकार इस व्यय ~~नीति~~ नीति में उचित ~~संसोधन~~ संशोधन द्वारा वितरणीय असमानताओं की कटुता को घटा सकती है। संशोधित व्यय नीति में छोटे पैमाने के ~~उद्~~ उद्योगों, श्रम-प्रधान उद्योगों तथा ग्रामीण उद्योगों को रियायत तथा प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

Scanned by CamScanner